

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 5217  
जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।  
2 श्रावण, 1941 (शक)

### शहरों में आईटी हब और बीपीओ

#### 5217. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के शहरों विशेषकर तमिलनाडु में स्थानीय स्तर पर आईटी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए आईटी हब स्थापित करने की किसी योजना पर कार्य कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार स्थानीय लोगों को आईटी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे शहरों में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) केंद्र खोलने का प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उत्तर

### इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

**(क) और (ख) :** विभिन्न शहरों में आईटी हब सृजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। तथापि, एमईआईटीवाई की एक स्वायत्त सोसाइटी, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) में प्राथमिक आईटी स्थल के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) योजना के अंतर्गत सांविधक सेवाएं प्रदान करते हुए आईटी/आईटीईएस यूनिटों को आकर्षित करने के लिए देशभर में अपने केन्द्रों की स्थापना की है। तमिलनाडु राज्य में 5 एसटीपीआई केन्द्र चल रहे हैं, जो चेन्नै, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिम्पुरम् और त्रिची में हैं।

**(ग) और (घ) :** छोटे शहरों और नगरों में रोजगार के अवसर पैदा करने और आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रसार करने के लिए सरकार ने दो बीपीओ प्रोत्साहन योजना नामतः इंडिया बीपीओ स्कीम (आईबीपीएस) और नॉर्थ इस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम (एनईबीपीएस) का शुभारंभ किया था। इन योजनाओं का लक्ष्य व्यवहार्यता अंतराल निधियन के रूप में प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 53,300 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। योजना का कार्यकाल 31.03.2019 तक था। इन योजनाओं की शुरुआत से कुल 52,972 सीटों के लिए बीपीओ/आईटीईएस यूनिटों की स्थापना हेतु 297 यूनिटों को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 226 यूनिटों ने अब तक टियर 2/3 शहरों में 30,000 से अधिक कुशल व्यक्तियों को सीधे रोजगार देकर देश के 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 44,880 सीटों के लिए प्रचालन शुरू कर दिया है। तमिलनाडु राज्य में कुल 5,890 सीटों के लिए 42, बीपीओ/आईटीईएस यूनिटों में प्रचालन शुरू कर दिया है, जो 6147 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।

\*\*\*\*\*